(iii) Organisation of training camps, workshops and field demonstration to expose the flower growers to the latest production and marketting technology.

(iv) Providing upto 50% subsidy on poly green-house to the flower growers.

In addition, the Government of India is implementing a Central Scheme on Commercial Floriculture under which the State of Himachal Pradesh is also a beneficiary. The State has been allocated one small Tissue Culture Unit in private sector for multiplication of quality planting material for distribution among farmers. The State has also been provided Rs. 10 lakhs under Area Expansion Programme for developing 100 ha. of cultivation.

High yielding varieties of mustard seed

1487. SHRI BHAGABAN MAJHI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether some high yielding varieties of mustard seeds have been developed;

(b) whether such seeds have been grown in the country on an experimental basis; and

(c) if so, where and what are the result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Two mustard varieties recently released for cultivation are Jai Kissan (Bio-902) and Rajat (PCR-7). Both the varieties have been grown in the states of Western Rajasthan, Gujarat and Western Maharashtra under irrigated conditions. Varieties Bio-902 gave an average yield of 1867 kg/ha. as compared to 1590 kg/ha. of Varuna and 1559 kg/ha. of Kranti. While variety PCR-7 yielded on an average 1907 kg/ha. against 1564 kg/ha. of Varuna and 1592 kg/ha. of Kranti. These varieties have given 17 to 20% higher seed yield over standard varieties like Varuna and Kranti in above mentioned states.

उर्वरकों और बीजों पर दी जाने वाली राजसहायता में कमी

1488. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान किसानों को उर्वरकों तथा बीजों पर दी जाने वाली राजसहायता में कमी की गई है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) कृषि उत्पादन पर किस सीमा तक प्रभाव पडा है ?

(घ) इस हानि की प्रतिपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार : (क) से (ङ) प्रमाणीकृत बीजों के वितरण पर राजसहायता विभिन्न फसल विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है। 1992-93 से नई किस्मों के प्रमाणीकृत बीजों के प्रयोग का प्रचार-प्रसार करने के लिए राजसहायता की भिन्न-भिन्न दरों को लागू किया गया था, फिर भी इससे फसल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 1992-93 और 1993-94 के दौरान तिलहनों तथा दलहनों के लिए राजसहायता की दर में कोई कमी नहीं हुई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए बीजों पर ढुलाई राजसहायता योजना भी है।

जहां तक उर्वरकों का संबंध है, भारत सरकार किसानों को रबी 1992-93 से विनियंत्रित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत, 1992-93 के दौरान 339.73 करोड़ रुपए और 1993-94 के दौरान 517.34 करोड़ रुपए की राशि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्मुक्त की गई चूंकि यह योजना उनके माध्यम से कार्यान्वित की गई थी। 1994-95 के दौरान, कृषि तथा सहकारिता विभाग, उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत बिक्री की रिपोर्टों के आधार पर सीधे भुगतान कर रहा है जिसके लिए अब तक 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि अनुमानित आवश्यकता 550 करोड़ रुपए की है।